SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं की संभावनाएं एवं चुनौतियाँ

अनामिका कुमारी, Ph.D., अर्थशास्त्र विभाग
ललित नारायण महिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
अनामिका कुमारी, Ph.D.
E-mail : manamika15786@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 29/11/2024
Revised on : 30/01/2025
Accepted on : 08/02/2025
Overall Similarity : 01% on 31/01/2025

शोध सार

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित अर्थवयवस्था है, मुख्यतः विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती होती है। कृषि आधारित होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्योगों की भागीदारी बढ़ध्ती जा रही है "खाद्य प्रसंस्करण" उद्योग मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है, जो मुख्य रूप से खाद्य विनिर्माण संस्थानों का समर्थन करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो की क्षमता को बढ़ाती है। बिहार मुख्य रूप से कृषि एवं पशु उत्पादन का बड़ा आधार है, जो मानव उपभोग के लिए प्रसंस्करण किये जाने वाले कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है। ''खाद्य प्रसंस्करण' उद्योग के लिए यह राज्य पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। बिहार राज्य के औद्योगिकीकरण में उच्च भुमिका निभाने की उम्मीद है।

मुख्य शब्द

कृषि उत्पाद, पूँजी की कमी, उन्नत किस्म, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार.

परिचय

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके यहाँ प्रचुर मात्रा में कृषि एवं पशु उत्पादन पाया जाता है जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए अत्यंत ही उपयोगी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का तात्पर्य वैसे क्रियाकलापों से है, जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों एवं पशु उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जा सके, जैसेः डेयरी उत्पाद, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बन्द भोजन तथा पेय पदार्थ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में शामिल किये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत जल्द खराब होने वाले अखाद्य पदार्थों को संसाधनों के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपयोगी एवं लंबे समय तक

उपयोग किये जा सकने वाले भोज्य या पेय पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, स्वाद और सुविधा पर भी विचार किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योंगों को पाँच भागों में बाँटा गया है, जिसमें अनाज और दालें, फल–सब्जियाँ, मांस और मुर्गी पालन, डेयरी उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल है।

संभावनाएँ

बिहार में 'खाद्य प्रसंस्करण' के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उधोगों की आपार संभावनाएँ खोजी जा सकती है। राज्य के मुख्य उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कर बाजार में उतारने की आवश्यकता है। राज्य में धान अधिक पैदावार होने के बावजुद उसकी प्रोसेसिंग दूसरे राज्यों में होने के बाद वह पुनः बिहार के बाजारों में आती है। ऐसे में अगर राज्य में ही प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाती है, तो उनके उत्पादों को उचित कीमत मिल सकता है। बिहार में मक्का उत्पादन भी बहुत वृहद पैमाने पर होता है, लेकिन उससे बनने वाले उत्पाद दूसरे राज्यों में तैयार किये जाते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के निदेशक का कहना है, कि पटना केन्द्र पर खाद्य प्रसंस्करणों के उत्पादों की जाँच की उचित व्यवस्था की जा रही है। अब उद्यमियों को अपने उत्पादों के जाँच के लिए अन्य राज्यों में नहीं भेजना होगा तथा यहाँ जाँच के बाद उद्यमी अपने उत्पादो को सीधा बाजारों में उतार सकेंगें ।

बिहार के सभी पंचायतों में लगेंगे फूड प्रोसेसिंग उद्योग

बिहार सरकार ने राज्य के सभी पंचायतो में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत नये उद्यमियों को 'खाद्य प्रसंस्करण' उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किघ्या गया है। बिहार के सभी 8387 पंचायतो मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आरंभ करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें उद्यमियों का चयन करके उनके उत्पादों का निरीक्षण जिला उद्योग समिति करेगा। इसमें युवा उद्यमी को पर्याप्त अवसर मिलेगा एवं बेरोजगार महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए युवा उद्यमी को पर्याप्त मात्रा में ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे खाद्य प्रोसेंसिंग उद्योगों को बढ़ावा मिले एवं ग्रामीण स्तर पर हीं रोजगार का सूजन हो सके जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन भी रुकेगा।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चुनौतियाँ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, कि इन क्षेत्रों की सभी चुनौतियों को दूर किया जा सके। ग्रामीण स्तर पर 'खाद्य प्रसंस्करण' सामाग्रियों का भंडारण क्षमता अधिकतम विकसित की जानी चाहिए, जिससे खाद्य पदार्थों का कम से कम नुकसान हो एवं ग्रामीण आबादी आत्मनिर्भर बन सके। अच्छी भंडारण सुविधाओं से किसानों को कई तरह से अपनी उपज को लामदायक बनाने का अवसर मिलेगा, जिसमे उपज को मंडियों, सहकारी समितियों और स्थानीय व्यापारियों को बेचना भी शामिल है।

खाद्य सेवा उद्योगों में सबसे बड़ी समस्याओं में से श्रम की कमी और स्टाफिंग की समस्याएं दे अधिक टर्न ओवर दरों से नये श्रमिकों को आकर्षित करने में कठिनाई होगी और इसका प्रभाव मुख्य रुप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर पड़ेगा। वर्तमान समय में बिहार में खाद्य सुरक्षा की दृष्टी से बड़ी समस्या गरीबी है, ऐसे में वे आर्थिक कमी के कारण पोषण युक्त भोजन नहीं खरीद सकते हैं।

बिहार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र छोटा होने के कारण खाद्य– प्रसंस्करण अभी तक केवल 10 प्रतिशत तक हीं पहुँच सका है, जिसका कारण है, अपर्याप्त तक बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति श्रृंखला का सही नहीं होना, इसके अन्तर्गत उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच विपरीत संबंध भी हैं, जिसके कारण गुणवत्ता और सुरक्षा मानको पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, कि 'खाद्य– प्रसंस्करण' में वे सभी चरण शामिल किये जाते

हैं, जिसमें कच्चे माल को खाद्य एवं पेय–पदार्थों में बदला जाता है। खाध– प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करता है, कि हमारे पास परिवारों के लिए स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन और पेय –पदार्थों की उपलब्धता आसानी से हो, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो ।

खाद्य प्रसंस्करण ने हमारी पहुँच को बहुत आसान कर दिया है, जिससे जल्द खराब होने वाले अखाद्य पदार्थों को संसाधनों के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपयोगी एवं लंबे समय तक उपयोग किया जाने वाला भोज्य या पेय– पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग बिहार, सरकार की बेब साइट, https://sfc.bihar.giv.in/ Accessed on 10/09/2024.
2. कृषि रोडमीजजचेरूध्धेबिण्इपींतण्हपअण्पदध्प्प, 2017– 22 बिहार सरकार, अध्याय–12 खाद्य प्रसंस्करण, पृ. 129–30।
3. आर्थिक सर्वेक्षण, 2015–16 वित्त विभाग, बिहार सरकार पटना, फरवरी 2016 पृ. 138।
4. वार्षिक औधोगिक सर्वेक्षण 2012–13 के आकड़ें ।

****